



राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022

प्रलिस के ललल:

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, सुदूर संवेदन/रमित सेंसिंग, SDG ।

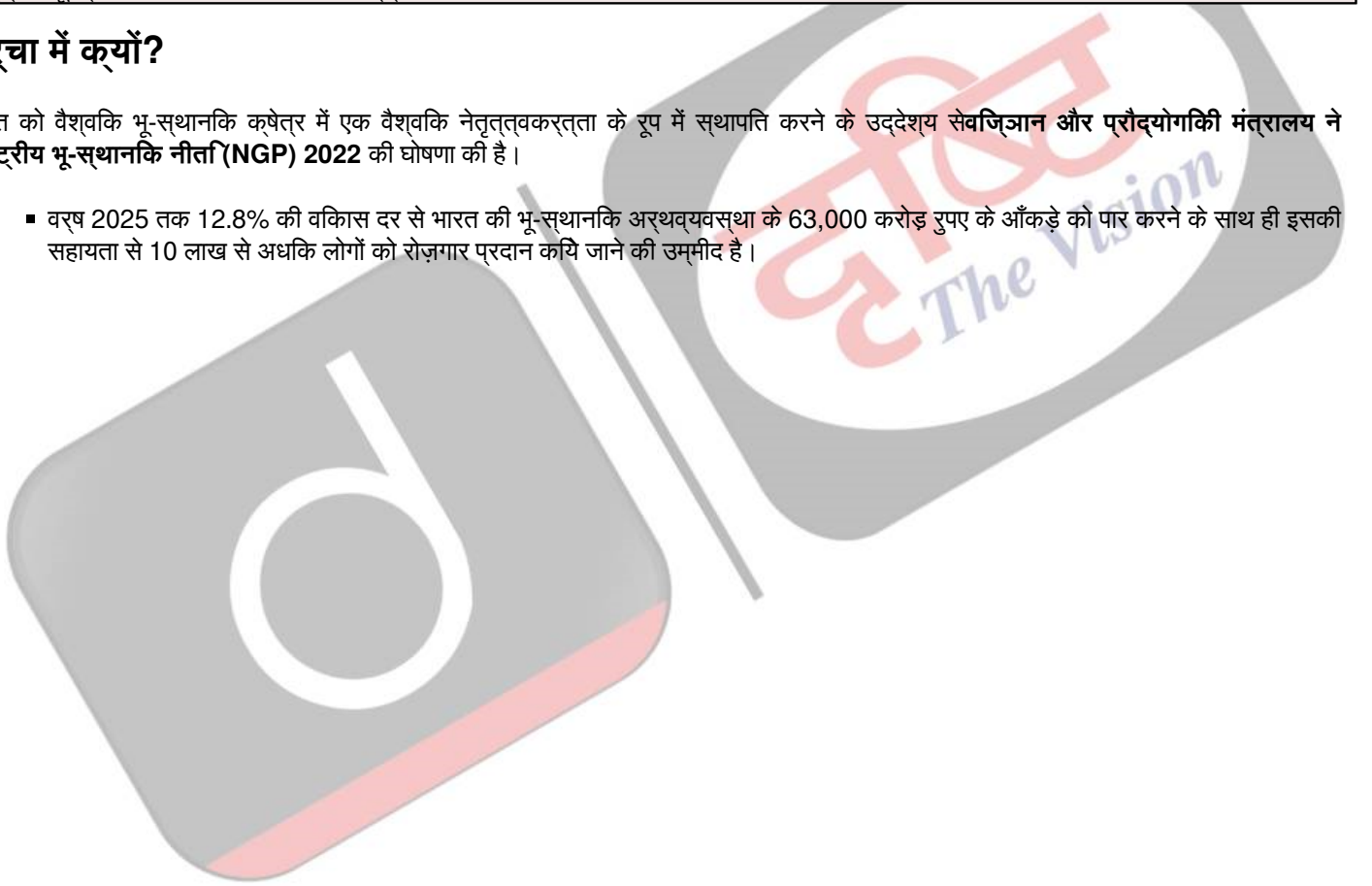
मेन्स के ललल:

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022, इसका महत्त्व और संबंधित चिंताएँ

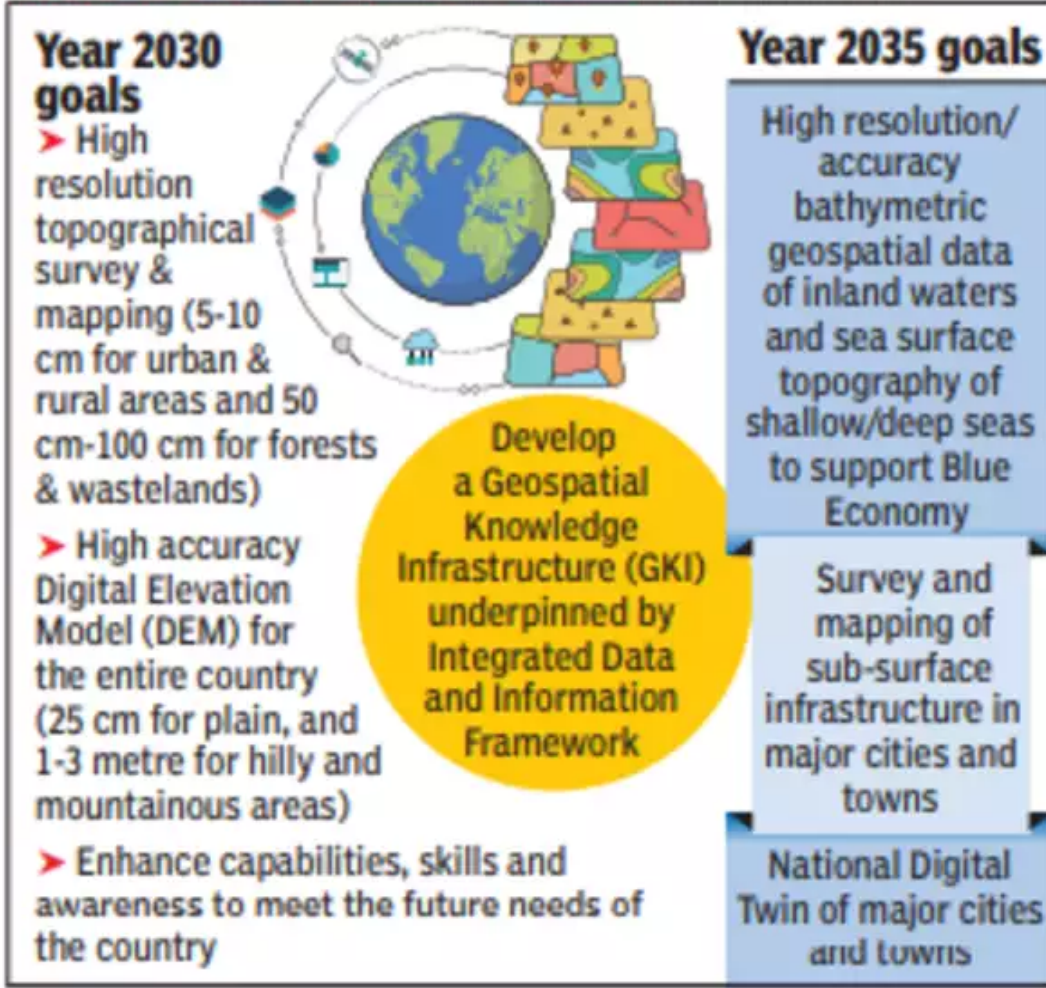
चर्चा में क्यों?

भारत को वैश्विक भू-स्थानिक क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से वल्लिज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (NGP) 2022 की घोषणा की है ।

- वर्ष 2025 तक 12.8% की विकास दर से भारत की भू-स्थानिक अर्थव्यवस्था के 63,000 करोड़ रुपए के आँकड़े को पार करने के साथ ही इसकी सहायता से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किये जाने की उम्मीद है ।



NATIONAL POLICY 2022 NOTIFIED



पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2021 में मानचित्र सहित भू-स्थानिक डेटा एकत्र करने और उनकी प्रसुततिके संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।
- जबकि दिशा-निर्देशों ने भू-स्थानिक डेटा एकत्रीकरण/उत्पादन/पहुँच को उदार बनाकर भू-स्थानिक क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त कर दिया है, नीति 2022 भू-स्थानिक पारितंत्र के व्यापक विकास के लिये एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022:

- परिचय:**
 - यह भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नागरिक-केंद्रित नीति है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि और एक संपन्न सूचना अर्थव्यवस्था को संवर्द्धित करने के लिये भू-स्थानिक क्षेत्र को मजबूत करना है।
 - इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्च सटीकता वाले डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) के साथ उच्च रिज़ॉल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मानचित्रण सुनिश्चित करना है।
- लक्ष्य एवं उद्देश्य:**
 - यह उच्च स्तरीय नवाचार पारितंत्र के साथ भारत को एक वैश्विक भू-स्थानिक नेता के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।
 - एक मजबूत राष्ट्रीय ढाँचे का निर्माण करना, जिसका उपयोग देश डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने और सार्वजनिक सेवाओं के बेहतर वितरण के लिये कर सकता है।
 - भू-स्थानिक अवसंरचना, भू-स्थानिक कौशल और ज्ञान, मानक, भू-स्थानिक व्यवसाय विकसित करना।
 - भू-स्थानिक सूचना के सृजन और प्रबंधन हेतु नवाचार को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करना।
- संस्थागत ढाँचा:**
 - राष्ट्रीय स्तर पर भू-स्थानिक डेटा संवर्द्धन और विकास समिति (Geospatial Data Promotion and Development Committee- GDPDC) भू-स्थानिक क्षेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित रणनीतियों को तैयार करने एवं लागू करने हेतु शीर्ष निकाय होगी।

- वर्ष 2021 में गठित GDPDC वर्ष 2006 में गठित राष्ट्रीय स्थानिक डेटा समिति (National Spatial Data Committee- NSDC) को प्रतस्थापित और इसके कार्यों एवं शक्तियों को समाहित करेगा।
- **वजिज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सरकार का नोडल विभाग बना रहेगा** तथा GDPDC भू-स्थानिक प्रशासन से संबंधित अपने कार्यों के निर्वहन में **DST को उपयुक्त सफ़ारिशें करेगा।**
- **वजिन को साकार करने हेतु नीतितगत नरिणयः**
 - वर्ष 2025:
 - **भू-स्थानिक क्षेत्रों के उदारीकरण और मूल्यवर्द्धति सेवाओं के साथ संवर्द्धति व्यावसायीकरण के लिये डेटा के लोकतन्त्रीकरण का समर्थन करने वाली एक सक्षम नीति एवं कानूनी ढाँचा तैयार कथिा जाए।**
 - वर्ष 2030:
 - **उच्च वभिदन स्थलाकृतिक सरवेक्षण और मानचित्रण** (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 5-10 सेमी. एवं जंगलों व बंजर भूमा हेतु 50-100 सेमी.)।
 - वर्ष 2035:
 - **ब्लू इकॉनमी का समर्थन करने के लिये उच्च वभिदन/सटीकता युक्त अन्तरदेशीय जल और उथले/गहरे समुद्र की सतह स्थलाकृतिक बाथमिटरिक भू-स्थानिक डेटा।**
 - **प्रमुख शहरों और कस्बों का नेशनल डजिटल ट्वनि (Twin)।** डजिटल ट्वनि एक भौतिक संपत्ति, प्रक्रिया या सेवा की एक आभासी प्रतकृति है जो नई डजिटल क्रांतिके केंद्र में है।
 - नेशनल डजिटल ट्वनि (Twin) स्मार्ट, डायनेमिक, कनेक्टेड डजिटल ट्वनिस का एक इकोसिस्टम होगा, जो बेहतर नरिणय लेने की सुवधि के लिये सुरक्षित और इंटरऑपरेबल (Interoperable) डेटा शेयरिंग द्वारा सक्षम होगा।
- **महत्त्वः**
 - भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और डेटा **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** को प्राप्त करने के लिये परिवर्तन एजेंटों के रूप में कार्य कर सकते हैं।
 - यह स्टार्टअप को बढ़ावा देने और बाह्य देशों पर निर्भरता को कम करने के लिये एक जीवन्त पहल है।
 - सैन्य संचालन, आपदा और आपातकालीन प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी, भूमि एवं शहर के लिये योजना जैसे महत्त्वपूर्ण डेटा प्रबंधन अनुप्रयोगों हेतु भू-स्थानिक डेटा आवृत्तियों के व्यापक स्पेक्ट्रम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संबंधित चिंताएँ:

- **जटिल डेटा:**
 - भू-स्थानिक डेटा को जटिल संबंधों वाले डेटा वषिय के रूप में उनके मध्य वर्णति कथिा जा सकता है।
 - ऐसा डेटा जसि अभी पूरी तरह से समझा और संबोधित कथिा जाना बाकी है, को सुरक्षित रखने में बड़ी चुनौतियाँ और अडचनें आती हैं।
- **सुरक्षा चिंताएँ:**
 - हालाँकि भू-स्थानिक डेटा तक पहुँच को प्रबंधित करने और साझा करने के लिये कई प्रकार के मॉडल एवं तकनीकें उपलब्ध हैं, लेकिन **राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने पर बहुत कम ध्यान दिया गया है**, जैसे- पहुँच नरिंत्रण (Access Control), प्रतभूतियाँ तथा गोपनीय नीतियाँ एवं वशिष रूप से रक्षा क्षेत्र की त्रि-सेवाओं (Tri-Services) में सुरक्षित अन्तरसंचालनीयता (Interoperable) GIS अनुप्रयोगों का विकास।
- **डेटा का दुरुपयोग और गोपनीयता का उल्लंघन:**
 - यदि वभिनिन रपिऑजटिरी से डेटा को एकीकृत करके भू-स्थानिक डेटा को पूरे नकिया को उपलब्ध कराया जाएगा, तो **संभावित डेटा के दुरुपयोग और गोपनीयता के उल्लंघन की गंभीर संभावनाएँ हैं।**
 - रक्षा अनुप्रयोगों के संदर्भ में एक प्रमुख चिंता का वषिय यह है कि "स्वामित्व नरिमाण जैसी संवेदनशील जानकारी भी प्रकट हो सकती है या महत्त्वपूर्ण बुनयिादी ढाँचे के बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से सुलभ हो सकती है।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी:

- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में भौगोलिक मानचित्रण और वशिलेषण हेतु **भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System- GIS)**, **ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (Global Positioning System- GPS)** और **रमिोट सेंसिंग** जैसे उपकरणों का उपयोग कथिा जाता है।
- ये उपकरण वस्तुओं, घटनाओं और परघटनाओं (पृथ्वी पर उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार अनुक्रमित जयिोटैंग) के बारे में स्थानिक जानकारी प्रदान करते हैं। किसी स्थान का डेटा स्थिर (Static) या गतशील (Dynamic) हो सकता है।
- किसी स्थान के स्थिर डेटा/स्टैटिक लोकेशन डेटा (Static Location Data) में **सडक की स्थिति, भूकंप की घटना या किसी वशिष क्षेत्र में बच्चों में कुपोषण की स्थिति के बारे में जानकारी शामिल होती है**, जबकि किसी स्थान के गतशील डेटा /डायनेमिक लोकेशन डेटा (Dynamic Location Data) में संचालित वाहन या पैदल यात्री, संक्रामक बीमारी के प्रसार आदि से संबंधित डेटा शामिल होता है।
- बड़ी मात्रा में डेटा में **स्थानिक प्रतरूप की पहचान के लिये इंटेलजेंस मैप्स (Intelligent Maps)** नरिमित करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग कथिा जा सकता है।
- यह प्रौद्योगिकी दुरलभ संसाधनों के महत्त्व और उनकी प्राथमिकता के आधार पर नरिणय लेने में मददगार हो सकती है।

आगे की राह

- आपदा नयिोजन परदृश्य में भाग लेने वाले व्यक्तियों और संगठनों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिये लागू किया जाना चाहिये कि उपयोगकर्ताओं एवं एप्स के पास केवल उसी डेटा तक पहुँच हो जिसकी उन्हें आवश्यकता है।
- **राष्ट्रीय भू-स्थानिकी नीति 2022** में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों हेतु सुरक्षा एक स्पष्ट रोडमैप और SOP तैयार किया जाना चाहिये, चाहे वह तीनों सैन्य सेवा, अर्द्धसैनिकी या महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा क्षेत्र हों।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'डिजिटल इंडिया' योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया।
2. एक नीतितगत ढाँचे की स्थापना जिससे बड़े आँकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई की सुविधा प्रदान करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

स्रोत: फाइनेंसियल एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-geospatial-policy-2022>

